



खोदते-खोदते खो रहे हैं पहाड़

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जब सरकार से पूछा कि उठा कर ले गए? तब सभी जगलक लोग चाँके कि इनी सारी पांचवी के बाद भी अरावली पर चल है अवैध खनन से किस तरह भारत पर खतरा है। असल में जब कोई पर्यावरणीय खतरा दिल्ली पर नहीं मंडलता, उसे अंभासा से लिया नहीं जाता। जान लें कि गुजरात के खेड ब्रह्म से शुरू होकर कोई 692 किमी तक फैली अरावली पर्वतमाला का विसर्जन देश के सबसे ताकतवर स्थान गयसीना हिल्स पर होता है जहां गट्टपति भवन खिलता है। अरावली पर्वतमाला को कोई 65 करोड़ साल पुराना माना जाता है और इसे दुनिया के सबसे प्राचीन पहाड़ों में एक गिना गया है। ऐसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षण का बड़ा हिस्सा तीव्र चार दशक में पूरी तरह केवल नदारद होता है। असल में अरावली पहाड़ रेगिस्तान से चलने वाली आधियों को रेकेने का काम करते रहे जैससे मरुपूर्ण का विस्तार नहीं हुआ एवं दूसरा इसकी जारी अप्रैली पर खनन से गेह का पालना आदेश सात मई 1992 को जारी किया गया। फिर सन 2003 में एमजी महता की याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई। कई ओरास और असल में एक लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र, होटल, रुमा मन्त्रालय की बड़ी आवासीय कोलेजी बना दी गई। अब जब दिल्ली में गर्मी के दिनों में पाकिस्तान से आ रही रेत की मान व तपन ने तंग करना शुरू किया तब यहां के सताधारियों को पहाड़ी की चिंता ढूँढ़ी देश में पर्यावरण संक्षण के लिए जगल, पानी बचाने की तो कई मुझम चल रही है, लेकिन मानव जीवन के विकास की कहानी के अधार रहे पहाड़-पतरों के नैरपीरी स्वरूप को पहाड़ का अब जीवी यथा धनार्जन का माध्यम रह गया है और पहाड़ निराश-हासा से अपनी अंतिम सास तक समाज को संबंधन के लिए सर्वांग कर रहे हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि वह अरावली पहाड़ियों के 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर रेक कराना और सरकार के लिए पहाड़ को अब जीवी यथा धनार्जन का माध्यम रह गया है। अब समझ में एक अपनी अंतिम सास तक समाज को संबंधन के लिए सर्वांग कर रहे हैं।

अरावली पर खनन से गेह का पालना आदेश सात मई 1992 को जारी किया गया। फिर सन 2003 में एमजी महता की याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई। कई ओरास और असल में एक लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र, होटल, रुमा मन्त्रालय की बड़ी आवासीय कोलेजी बना दी गई। अब जब दिल्ली में गर्मी के दिनों में पाकिस्तान से आ रही रेत की मान व तपन ने तंग करना शुरू किया तब यहां के सताधारियों को पहाड़ी की चिंता ढूँढ़ी देश में पर्यावरण संक्षण के लिए जगल, पानी बचाने की तो कई मुझम चल रही है, लेकिन मानव जीवन के विकास की कहानी के अधार रहे पहाड़-पतरों के नैरपीरी स्वरूप को पहाड़ का अब जीवी यथा धनार्जन का माध्यम रह गया है और पहाड़ निराश-हासा से अपनी अंतिम सास तक समाज को संबंधन के लिए सर्वांग कर रहे हैं।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि वह अरावली पहाड़ियों के 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर रेक कराना और सरकार के लिए पहाड़ को अब जीवी यथा धनार्जन का माध्यम रह गया है। अब समझ में एक अपनी अंतिम सास तक समाज को संबंधन के लिए सर्वांग कर रहे हैं।

अब समझ में आ रहा है कि नट किरण गए पहाड़ के साथ उससे जुड़ा पूरा पर्यावरणीय तंत्र ही नष्ट हो गया है। खनिज के लिए, सड़क व पुल की जमीन के लिए या फिर निर्माण सामग्री के लिए, बस्ती के

लिए, विस्तार के लिए, जब जमीन बची नहीं तो लोगों ने पहाड़ों का सबसे सत्ता, सुलभ व सहज जस्ता मान लिया। उस पर किसी की दावेदारी भी नहीं थी। सतपुड़ा, मेकल, पश्चिमी घाट, हिमालय, कोई भी पर्वतमालाएं लें, खनन ने पर्यावरण को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। रेल मार्ग या हाईवे बनाने के लिए भी पहाड़ों को मनमाने तोके से बास्ट दें उड़ाने वाले इंजीनियर इस तथ्य को शान्तिता से नजरअंदाज कर देते हैं कि पहाड़ स्थानीय पर्यावास, समाज, अर्थ व्यवस्था, आस्था, विश्वास का प्रतीक होते हैं। पारंपरिक समाज भले ही इनी तोकीन क न जानता हो, लेकिन इंजीनियर तो जानते हैं कि धरती के दो भाग जब एक दूसरे की तरफ बहे हैं तो प्रदेश के 19 जिलों में खनन को प्रसाद भवत्ता के चांगे से बद करना पड़ता है। हजारों हजार साल में गांव-शहर बनने का मूल अधार वहां पानी की उपलब्धता होता था। पहले नदियों के किनारे सम्भवत आई, फिर ताल-तरैयों के तट पर बसिया गया। किसी भी आंचलिक गांव को देखें, जहां नदी का तट नहीं है कुछ पहाड़, पहाड़ के निचले दिस्तों में झील व उसे खेकर बीची बरितियों का ही भूगोल दिखाया है। हिस्सा पर शुरू बनानी है अभी सौ साल पर लेते तक शहर के चांगे से एप पहाड़ थे, हैं भूमि खाली उड़ाइ देखा गया। अब कम बारिश होने पर भी तालाब लबलाब। बीते चार दशकों में तालाबों की जो दुपात छुँड़ सा छुँड़, अब पहाड़ पर गांव-शहर बनानी है तो सरी पहाड़ी की अपने में समेटने का काम वहां की हीरायी लड़ाई होती है। भरी गर्मी में भी वहां की शाम ठंडी होती और कम बारिश होने पर भी तालाब लबलाब। बीते चार दशकों में तालाबों की जो दुपात छुँड़ सा छुँड़, अब पहाड़ पर गांव-शहर बनानी है तो उसी पहाड़ी की अपनी खाली उड़ाइ होती है। यह जानियां हैं कि इलाके के पहाड़ पर हाईवे से ही हुआ है। यह विडंबना के भूखलन से कहीं कुछ लेना-देना ही थी नहीं। किसी पहाड़ी की ताड़ियों से इलाके के भूखल स्तर पर असर पड़ता है। उसके बाद जीवन एवं चेहरे जीवन एवं चेहरे जी होती है।

पंकज चतुर्वेदी
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

मालदीव को साधना जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इडाहिम मोहम्मद सोलेह के शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मोदी का यह कदम दोनों देशों को फिर से करीब लाने में मदद करेगा और इस देश पर चीन के प्रभुत्व को कमज़ोर करने में सहायक सिद्ध होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 नवंबर को मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इडाहिम मोहम्मद सोलेह के शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भारत ने मोदी की याचा को नेबरहूड फर्ट नीति के तहत बताया है। माना जा रहा है कि मालदीव में नए सरकार के गठन के बाद भारत-मालदीव रिश्तों को पटरी पर लाने की काशिश भी रेज होगी। गैरतलब है कि मालदीव से पिछले कुछ सालों में रिश्तों में काफी खटास आ गई थी। चीन का दखल बढ़ने के साथ ही भारत की भूमिका पर सावल खड़े किए जा रहे थे। भारतीयों से भेदभाव, उन्हें वीजा और रोजगार न देने के मालमों में दोनों देशों के रिश्तों में दरार पैदा कर दी थी। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को चीन का समर्थक माना जा रहा था। भारत व अमेरिका के विरोध के बाजूद यामीन ने मालदीव में आपातकाल लागू कर विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेज दिया था। हाल में दुपर युनाव में यामीन को चीन का समर्थक मान रहा है। भारत और चीन दोनों चाहते हैं कि उनकी नौसेनिक रणनीति के दायरे में यह इलाका रहे। भारत पिछले कुछ सालों से मालदीव से दूर होता गया। इसकी वजह यह रही कि अब्दुल्ला यामीन की सरकार को चीन ज्यादा रास आया और उन्होंने भारत से साथ भेदभाव किया। करीब चार लाख की आवादी वाले इस देश में यामीन की खुशी को पुरा करने के लिए एक लाल बुलावा लगा। इस बाद भी एसोसिएशन को चीन का समर्थक माना जा रहा है। भारत और चीन दोनों चाहते हैं कि उनकी नौसेनिक रणनीति के दायरे में यह इलाका रहे। भारत पिछले कुछ सालों से मालदीव से दूर होता गया। इसकी वजह यह रही कि अब्दुल्ला यामीन की सरकार को चीन ज्यादा रास आया और उन्होंने भारत से साथ भेदभाव किया। करीब चार लाख की आवादी वाले इस देश में यामीन की खुशी को पुरा करने के लिए एक लाल बुलावा लगा। इस बाद भी एसोसिएशन को चीन का समर्थक माना जा रहा है। भारत और चीन दोनों चाहते हैं कि उनकी नौसेनिक रणनीति के दायरे में यह इलाका रहे। भारत पिछले कुछ सालों से मालदीव से दूर होता गया। इसकी वजह यह रही कि अब्दुल्ला यामीन की सरकार को चीन ज्यादा रास आया और उन्होंने भारत से साथ भेदभाव किया। करीब चार लाख की आवादी वाले इस देश में यामीन की खुशी को पुरा करने के लिए एक लाल बुलावा लगा। इस बाद भी एसोसिएशन को चीन का समर्थक माना जा रहा है। भारत और चीन दोनों चाहते हैं कि उनकी नौसेनिक रणनीति के दायरे में यह इलाका रहे। भारत पिछले कुछ सालों से मालदीव से दूर होता गया। इसकी वजह यह रही कि अब्दुल्ला यामीन की सरकार को चीन ज्यादा रास आया और उन्होंने भारत से साथ भेदभाव किया। करीब चार लाख की आवादी वाले इस देश में यामीन की खुशी को पुरा करने के लिए एक लाल बुलावा लगा। इस बाद भी एसोसिएशन को चीन का समर्थक माना जा रहा है। भारत और चीन दोनों चाहते हैं कि उनकी नौसेनिक रणनीति के दायरे में यह इलाका रहे। भारत पिछले कुछ सालों से मालदीव से दूर होता गया। इसकी वजह यह रही कि अब्दुल्ला यामीन की सरकार को चीन ज्यादा रास आया और उन्होंने भारत से साथ भेदभाव किया। करीब चार लाख की आवादी वाले इस देश में यामीन की खुशी को पुरा करने के लिए एक लाल बुलावा लगा। इस बाद भी एसोसिएशन को चीन का समर्थक माना जा रहा है। भारत और चीन दोनों चाहते हैं कि उनकी नौसेनिक रणनीति के दायरे में यह इलाका रहे। भारत पिछले कुछ सालों से मालदीव से दूर होता गया। इसकी वजह यह रही कि अब्दुल्ला यामीन की सरकार को चीन ज्यादा रास आया और उन्होंने भारत से साथ भेदभाव किया। करीब चार लाख की आवादी वाले इस देश में यामीन की खुशी को पुरा करने के लिए एक लाल बुलावा लगा। इस ब

